

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकठोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

फिर रंग बदलेगी महाराष्ट्र की सियासत ?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा तय

फडणवीस के साथ तस्वीर पर उद्धव का बड़ा बयान...

6 अप्रैल को करेंगे रामलला के दर्शन, तैयारियां शुरू...



मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे-ऐसे रंग देखे हैं जिनकी पहले कल्पना भी करना मुश्किल था। कभी देवेंद्र

फडणवीस और अजित पवार साथ में शपथ लेते नजर आए, कभी कट्टर विरोधी रही शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, और कभी

फडणवीस से मुलाकात पर उद्धव का बड़ा बयान

देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा, 'पहले एक खुलापन था। आज ऐसा कहते हैं कि बंद दरवाजे के भीतर जो चर्चा होती है, वह लाभदायक होती है, इसलिए हमारी फिर कभी बंद दरवाजे के भीतर चर्चा हुई तब बात करेंगे।' यह पूछे जाने पर कि क्या यह कोई संकेत है, उद्धव ने कहा, 'ऐसा कुछ नहीं है। मैं और वह विधानभवन के गेट पर आ रहे थे और उस समय जिसे राम-राम या हेलो कहते हैं, वह हुआ।'

बालासाहेब की अभेद्य मानी जाने वाली शिवसेना के 2 टुकड़े हुए। अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर सूबे के सियासी गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक तस्वीर में साथ-साथ मुस्कुराते नजर आए हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। आगामी छह अप्रैल को वे अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद संभालने के ठीक बाद वे पत्नी और परिवार को लेकर कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे भी अयोध्या के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके चचेरे भाई और प्रतिद्वंद्वी राज ठाकरे ने भी अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया था, मगर स्थानीय सांसद के विरोध के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राजनेताओं की अयोध्या यात्रा हिंदुत्व और राममंदिर आंदोलन के लिए पूरा समर्पण होने के संकेत के तौर पर देखी जाती है।

एकनाथ शिंदे ने इस पिछले साल इस बात का ऐलान किया था कि वो जल्द ही अयोध्या में भगवान



राम के दर्शन करने लिए जायेंगे। अयोध्या दौरे के लिए तैयारियां भी जानकारी के मुताबिक सीएम के शुरू कर दी गयी हैं।

कामाख्या देवी के दर्शन करने भी गए थे

इसके पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी जाकर कामाख्या देवी के दर्शन भी किए थे। उस समय भी शिंदे के साथ इक्का-दुक्का नेताओं को छोड़कर सभी सांसद और विधायक गए थे। शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार की स्थापना के बाद यह स्पष्ट किया था की वो कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। अब शिंदे ने अयोध्या दौरे को लेकर कही बात को पूरा करने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व और बालासाहेब ठाकरे के विचारों को छोड़ने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने बगावत के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। शिंदे के इस अयोध्या दौरे हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी नेता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, शिंदे हमेशा यह कहते रहे हैं कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों की हैं। जहां सबको न्याय मिलेगा।

'क्या किसी को हाय-हेलो कहना पाप हो गया है?'

जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि क्या आज के हाय-हेलो के बाद आपका मोदी विरोध कम हो जाएगा, उद्धव ने कहा, 'नहीं, आप जल्दबाजी में ऐसी बड़ी बात मत करिए। क्या आज किसी को हाय-हेलो कहना पाप हो गया है? क्या किसी मकसद के साथ ही ऐसा करना चाहिए?' बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री पद संभालने को कहा गया था। शिंदे की बगावत के बाद उद्धव को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था।

माहिम में समुद्र तट पर बनी रहस्यमयी दरगाह (छिल्ला) पर चला बुलडोजर

मुंबई: मुंबई में माहिम के तट पर अनधिकृत रूप से बनाई जा रही दरगाह जैसे ढांचे को प्रशासन ने आज गिरा दिया। मुंबई शहर के रेजिडेंट कलेक्टर सदानंद जाधव ने बताया कि '(छिल्ला)' और उसके आसपास का ढांचा राजस्व विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। उन्होंने बताया कि BMC और मुंबई पुलिस के कर्मियों की मदद से ढांचे को गिराने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। जाधव ने बताया, हूबीएमसी ने अवैध ढांचे को गिराने के लिए मशीनरी मुहैया कराई और मुंबई

पुलिस ने सुरक्षा दी।'

कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने सुबह घटनास्थल का दौरा किया था, जिसके बाद ढांचा गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। 12 से 13 मजदूर हाथों में हथौड़ा छेनी लेकर पुलिस बल के साथ दरगाह (छिल्ला) के पास पहुंचे। 2 बुलडोजर के साथ उन्होंने तोड़ने की करवाई शुरू की। रमजान शुरू हो रहा है ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए किसी को भी समुद्री किनारे पर रुकने नहीं दिया गया और



महज 1 घंटे में पुलिस बल की मदद से पूरा मलबा हटा दिया गया।

'600 साल पुरानी दरगाह (छिल्ला) तोड़ी'

उठाया था दरगाह का मुद्दा

बता दें कि कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की अपनी रैली में अवैध दरगाह (छिल्ला) का मामला उठाया था। राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर अवैध दरगाह (छिल्ला) को नहीं तोड़ा गया तो वो वहां पर गणपति मंदिर की स्थापना कर देंगे। राज ठाकरे की स्पीच के बाद आज सुबह से मुंबई का प्रशासन हरकत में आ गया है। सुबह से ही अफसरों की टीम माहिम दरगाह (छिल्ला) में मौजूद है।

वहीं, इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में गुस्सा है। दरगाह किनारे रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके भी घर तोड़ दिए गए हैं। उनका कहना है कि 600 साल पुरानी दरगाह (छिल्ला) तोड़ दी गई। महिमा दरगाह बाबा के उस्ताद थे। देख रेख की लेकिन उन्होंने भी करवाई नहीं रोकी और दरगाह (छिल्ला) को तोड़ दिया गया है। राज ठाकरे ने अपने भाषण में

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

**सत्ता पक्ष और विपक्ष
छोड़ें अपनी जिद**

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, उससे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के बिना किसी विशेष कामकाज के खत्म होने की आशंका बढ़ गई है। यद्यपि दोनों पक्षों के बीच सहयोग-समन्वय कायम करने के प्रयत्न किए गए हैं,

लेकिन स्थिति जस की तस है। जहां सत्तापक्ष को राहुल गांधी की माफी से कम कुछ मंजूर नहीं है, वहीं विपक्ष अदाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किए जाने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। सत्तापक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर क्षमा याचना के बाद ही संसद चलने की संभावना जता रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि अदाणी मामले में बीच के किसी रास्ते की गुंजाइश ही नहीं है। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मांग को लेकर इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनके पीछे लौटने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। अब संसद तभी चल सकती है, जब दोनों पक्ष या तो एक-दूसरे की मांग मानें या फिर अपनी-अपनी मांग छोड़ें। चूंकि ऐसा होता नहीं दिखता, इसलिए संसद चलने के आसार नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की इसमें दिलचस्पी ही नहीं रह गई है कि संसद चले और वित्त विधेयक पर बहस होने के साथ प्रस्तावित विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़े।

यदि पक्ष-विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का यह सत्र बिना किसी कामकाज के खत्म हो जाता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। संसद की कार्यवाही में प्रति मिनट लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन बात केवल धन की बबार्दी की ही नहीं, आवश्यक विधेयक अटके रहने से राष्ट्र को होने वाली क्षति की भी है। वैसे तो इस क्षति की चिंता दोनों पक्षों को करनी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक सत्तापक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि संसद चलाने का दायित्व उसका ही होता है।

यह संभवतः पहली बार है, जब सत्तापक्ष के हंगामे के कारण भी संसद नहीं चल पा रही है। सत्तापक्ष को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि देश की जनता को यह संदेश जा रहा है कि उसकी रुचि संसद चलाने में नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय हितों को देने के उसके संकल्प की पूर्ति तभी होगी, जब वह संसद चलाने को लेकर प्रतिबद्ध दिखेगा।

जैसे सत्तापक्ष को राहुल गांधी की माफी को नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही विपक्ष को भी अदाणी मामले की जांच जेपीसी से कराने की जिद नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक छह सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति उन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने में समर्थ है, जो विपक्ष उठा रहा है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संयुक्त संसदीय समितियां किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय दलगत राजनीति का अखाड़ा भर बनकर रह जाती हैं।

editor@rokhoklekhaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

**नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करनेवाले
आम कारोबारियों के खिलाफ एफडीए भी अलर्ट**

मुंबई, बगीचों में अभी आम पके नहीं हैं लेकिन बाजार कई किस्म के आम से पट गए हैं। सिंदूरी, लंगड़ा, मालदा समेत अन्य किस्म के आम बाजार में दिखने लगे हैं। मंडी में आंध्रप्रदेश, ओडिशा, बंगाल सहित अन्य दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर आम मंगाए जा रहे हैं। इन्हें कार्बाइड से पकाकर बाजार में सजाया जा रहा है। समय से पहले बाजार में उतारे गए आम एक तो खाने में कम मीठे हैं, दूसरा ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। बाजार में मिलनेवाला केमिकलयुक्त आम लोगों को बीमार कर रहा है, जबकि व्यवसायी वर्ग को सिर्फ अपनी आमदनी नजर आ रही है। लोगों की सेहत से उनका



कोई लेना-देना नहीं है, वहीं आम नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करनेवाले आम कारोबारियों के खिलाफ एफडीए भी अलर्ट हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई व्यापारी केमिकल और

कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो यह बॉडी के नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, जो सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। दरअसल, फल कारोबारी

कच्चे आम के बगीचे खरीदते हैं। इसके बाद पेड़ से कच्चा आम तोड़ लिया जाता है। इसे नेचुरल दिखाने के लिए कारोबारी आम को गर्म जगह, जैसे बोरे, भूसे में भरकर रखता है। कुछ लोग इसमें कार्बन मोनो ऑक्साइड, एसिटलीन गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है।

एफडीए अतिरिक्त आयुक्त शशिकांत केकरे के मुताबिक, बाजार में बेमौसम मिलने वाले आम को लेकर एफडीए अलर्ट मोड पर है। एफडीए अधिकारी एक अभियान के तहत बाजार में मिलनेवाले आम की जांच कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने मनपा को लगाई जबरदस्त फटकार



मुंबई, महानगर मुंबई में पैदल चलनेवालों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने मनपा को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने मनपा को साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि बांद्रा-पूर्व के रहनेवाले लोगों को जल्द से जल्द स्काईवॉक उपलब्ध कराएं। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि फुटपाथ नहीं होने की स्थिति में लोग वैद्यसे और कहां पर पैदल चलेंगे?

बांद्रा-पूर्व में वर्ष २००८-०९ में एमएमआरडीए ने स्काईवॉक बनाया था। मुंबई का यह पहला स्काईवॉक था। यह बांद्रा स्टेशन से कलानगर चौक तक बनाया गया था। शुरू में लोगों ने इसका जमकर उपयोग किया। लेकिन बाद में इसकी जर्जर हालत के चलते लोगों ने नीचे से चलना शुरू किया। किंतु पिछले कुछ वर्षों

से इस स्काईवॉक को मनपा ने तोड़ दिया है और नीचे फुटपाथ पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। तमाम अतिक्रमण और अवैध कब्जे के चलते लोग ठीक से फुटपाथ पर चल नहीं सकते हैं, जिसे लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फटकार लगाई है।

कोर्ट ने मनपा को बांद्रा-पूर्व में एक स्काईवॉक बनाने का तत्काल निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ की अनुपस्थिति के कारण होनेवाली किसी भी अप्रिय दुर्घटना की रिपोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में मनपा यहां होनेवाली अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्डा की खंडपीठ ने मनपा को कड़े शब्दों में सुनाते हुए कहा कि सुरक्षित फुटपाथ की अनुपलब्धता के कारण होने वाली किसी भी शारीरिक चोट या मृत्यु को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए इस तरह की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मनपा का सार्वजनिक कर्तव्य और पूर्ण दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि मनपा को यात्रियों के प्रति अपने दायित्व और जवाबदेही को स्वीकार करना जरूरी है।

**सिंगर सोनू निगम के पिता
अगम कुमार निगम के घर से
72 लाख रुपये की चोरी**

मुंबई, गायक सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के आवास पर 72 लाख रुपये की चोरी होने की खबर सामने आई है। सोनू निगम के पिता को पूर्व ड्राइवर रेहान पर शक है। पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके (रेहान) खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, आरोपी रेहान की तलाश जारी है। अधिकारी ने बताया कि गायक के पिता अगमकुमार निगम अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में विंडसर ग्रैंड बिल्डिंग में रहते हैं और कथित चोरी 19 मार्च से 20 मार्च के बीच हुई। उन्होंने बताया कि सोनू की छोटी बहन निकिता ने बुधवार तड़के कथित चोरी की शिकायत ओशिवारा पुलिस थाने में दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, अगमकुमार के पास लगभग आठ महीने से रेहान नाम व्यक्ति ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था।

प्रत्येक व्यक्ति को २०२४ तक घर देने का दावा: आवास मंजूर होने के बाद भी नागरिकों को दर-दर भटकना पड़ रहा है!

मुंबई, सरकार ने राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को २०२४ तक घर देने का दावा कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है लेकिन इस योजना का लाभ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। ईडी सरकार के दावे फेल हो रहे हैं। आवास मंजूर होने के बाद भी नागरिकों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। इस योजना के तहत बीड जिले मंजूर हुए घर को पाने लिए भूख हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले को विधान परिषद में विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे ने उपस्थित किया था। दानवे के जवाब में ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि आवास योजना के लिए मंजूर हुई जगह अन्य प्रयोजन के लिए ध्यान में आने के बाद



संबंधित लोगों को दूसरी जगह पर आवास योजना को मंजूरी दी गई थी। इस दरम्यान संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को आवास देने का निर्णय लिया गया है लेकिन इस मामले में कई लोग न्यायालय में भी गए हैं। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचारार्थ है।

सवाल के जवाब में महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष २०२४ तक सभी घर देने की योजना जाहिर की है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार का १४ लाख १८ हजार ७८ का लक्ष्य है। इसमें से १४ लाख १६ हजार २३ आवास को मंजूरी दी गई है, बाकी २०५५ आवास की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू है। ऐसा महाजन ने बताया।

राज्य में अब तक ९९ लाख ३ हजार ७९१ आवास पूरे किए गए हैं। आवास के लिए जगह उपलब्ध कराने, आवास निर्माण के लिए मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार आदि के माध्यम से आवास निर्माण के काम को गति देने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।

10 देशों से भड़काई जा रही है खालिस्तान की चिंगारी खालिस्तान आंदोलन को हवा देने के लिए ९ ग्रुप सक्रिय

मुंबई, खालिस्तान समर्थक और 'वारिस दे पंजाब' का मुखिया अमृतपाल सिंह इन दिनों हिंदुस्थान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। इसी के साथ अलग-अलग देशों से भारतीय उच्चायोग पर हमले की खबरें आ रही हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों से पता चला है कि पंजाब में आतंकवाद और अशांति फैलाने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। करीब १० देशों से खालिस्तान की चिंगारी भड़काई जा रही है, जिनमें पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी और प्रशांस में

बैठे अलगाववादी कमांडर शामिल हैं। खालिस्तान आंदोलन को हवा देने के लिए ९ ग्रुप सक्रिय हैं।

बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल फरार चल रहा है। पिछले पांच दिनों से पंजाब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अमृतपाल के समर्थकों की गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन वह हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, खालिस्तानी समर्थक हिंदुस्थान ही नहीं दुनिया के कई देशों में सक्रिय हैं और देश में अशांति फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तीन अलगाववादी संगठन इस षड्यंत्र में



शामिल हैं। रणजीत सिंह नीता की अगुवाई में 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स', वाधवा सिंह बब्बर का 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' और परमजीत सिंह पांजवार के नेतृत्व में 'खालिस्तान कमांडो फोर्स' सक्रिय है। इसी तरह लंदन में हरदीप सिंगर निजारा का 'खालिस्तान टाइगर फोर्स'

संचालित हो रहा है। कनाडा से गुरजीत सिंह चीमा का 'खालिस्तान लिबरेशन फोर्स', जर्मनी से गुरमीत सिंह बग्गा और भूमिंदर सिंह भिंद्र के नेतृत्व में 'केजेडएफ' सक्रिय है जबकि यूके से गुरशरणवीर सिंह, इटली से गुरजिंदर सिंह और प्रशांस से पुरुषोत्तम सिंह की अगुवाई में

खालिस्तान आंदोलन को रसद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अन्य देशों में भी इनकी शाखाएं फैली हुई हैं।

असल में कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में खालिस्तानी कथित 'जनमत संग्रह' का दूसरा चरण आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत तब हुई थी, जब लंदन हाई कमीशन में हिंदुस्थान का झंडा नीचे उतार दिया गया था। उस एक घटना के बाद सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका के सैन प्रैंसिसको में भारतीय दूतावास पर हमला किया गया। उस वीडियो में तो अमृतपाल के बड़े-बड़े पोस्टर

भी देखे गए थे। एक ही नेरेटिव को सेट करने के लिए लगातार ट्विटर-व्हाट्स ऐप जैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। हैशटैग को इस नेरेटिव का बड़ा हथियार बनाया गया है।

तय रणनीति के मुताबिक, कुछ हैशटैग का इस्तेमाल हर उस अकाउंट से किया गया है, जो लगातार खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। दो दिनों के भीतर २८.५ फीसदी ट्वीट अमेरिका से आए थे, वहीं ८.९ प्रतिशत ट्वीट कनाडा से आए हैं। खालिस्तान के समर्थन के लिए तय रणनीति के तहत टूलकिट तैयार की जा रही है।

फर्जी रेड को अंजाम, तीन इंस्पेक्टर रैंक के अफसर बर्खास्त



मुंबई, महाराष्ट्र जीएसटी कार्यालय में काम करने वाले तीन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को वरिष्ठ अफसर राजीव मित्तल ने डिसमिस(बर्खास्त) कर दिया है। दरअसल मित्तल को यह जानकारी मिली थी कि यह इंस्पेक्टर फर्जी रेड में शामिल थे साथ ही इन लोगों ने एक ट्रेडर से 11 लाख रुपये भी लिए थे। बर्खास्तगी की इस कार्रवाई का बाकायदा अखबार में विज्ञापन भी दिया गया है। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक किसी अधिकारी को बर्खास्त कर उसकी जानकारी विज्ञापन के जरिये लोगों को दी गई हो। राजीव मित्तल ने बताया कि तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ सभी कानूनी और कागजी कार्रवाइयों के

बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल तीनों अफसरों के खिलाफ पुलिस की जांच शुरू रहेगी। मित्तल ने बताया कि हमारी तरफ से हमने एक डिपार्टमेंटल जांच शुरू की थी। उन्हें शो कॉज नोटिस दिया था। तमाम जांच पड़ताल के बाद यह तय हुआ कि विभाग की छवि को दागदार होने से बचाने के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया जाये।

इस मामले में बर्खास्त किये गए तीनों अधिकारियों के नाम हितेश वसईकर, मच्छिंद्र कांगने और प्रकाश शेगर् है। तीनों ने मुंबई के एक नामी ट्रेडर के यहाँ पर फर्जी रेड डाली और बाद में उससे 11 लाख रुपये की रिश्वत लेकर वहाँ से गए।

इस मामले में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितम्बर 2021 को तीनों जीएसटी अफसरों और एक अन्य आदमी को एक्सटॉर्शन और चीटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीनों अधिकारियों ने 14 जून 2021 को कालबादेवी के एक ट्रेडर के ऑफिस का निरीक्षण किया था। यह अधिकारी लालचंद वाणीगोता नाम के व्यापारी के ऑफिस में यह खाकर घुसे कि वो जीएसटी अधिकारी हैं।

आईटी सेक्टर के लगभग एक लाख युवा बेरोजगार हुए!



मुंबई, देश में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार रोजगार सृजन के मामले में कारगर उपाय करने में असफल साबित हो रही है। एक तरफ जहाँ नए रोजगार सृजन की गुंजाइश न्यूनतम स्तर पर है, वहीं आईटी सेक्टर में लाखों युवा बेरोजगार की कगार पर हैं। पिछले कुछ महीनों में आईटी सेक्टर के देश में लगभग एक लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। इतना ही नहीं यूबीएस और सुइस बैंक के मर्जर से भी फाइनेंशियल टेक्नो हब इंडिया को झटका लग सकता है। मोदी सरकार देश में भले रोजगार पैदा करने को लेकर रोज नए-नए दावे घोषित करे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो इस वर्ष की पहली तिमाही में नए रोजगार सृजन की रिपोर्ट पिछले २०

महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस वर्ष जनवरी माह में रोजगार सृजन का आंकड़ा अपने २० माह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे रोजगार के बाजार पर दबाव के संकेत मिलते हैं। एक दिन पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। ईपीएफ में नए मासिक सदस्यों की संख्या दिसंबर के ८,४०,३७४ से ७.५ प्रतिशत घटकर जनवरी में ७,७७,२३२ रह गई। फरवरी में यह आंकड़ा ५ प्रतिशत और गिर गया है। ईपीएफ में शामिल होनेवाले नए सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष मई २०२१ के बाद सबसे कम संख्या है। मई में महज ६,४९,६१८ सदस्यों ने नए पंजीकरण किए थे।



'गद्दे' गिरोह का पदार्पाश

दिल्ली, अपराध शाखा ने नाबालिगों के एक ऐसे गिरोह का पदार्पाश किया है जो लूटपाट से पहले पीड़ित के साथ समलैंगिक संबंधों के लिए दबाव डालते था। अगर पीड़ित मना कर देता था तो आरोपी मारपीट और लूटपाट कर फरार हो जाते थे।

आरोपी चोरी की स्कूटी पर लूटपाट व झपटमारी करते थे। आरोपियों ने टॉय गन रखी हुई थी। अपराध शाखा ने गिरोह के तीन नाबालिगों को पकड़ा है। इनमें से दो की उम्र तो सिर्फ 15 वर्ष है। तीसरे आरोपी की उम्र 17 वर्ष और आठ महीने है।

पुलिस के अनुसार, नोएडा की निजी कंपनी में काम करने वाले युवक ने 12 मार्च को शिकायत दी थी कि वह गली के बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रहा था, तभी स्कूटी पर तीन युवक आए और समलैंगिक

संबंधों बनाने के लिए कहने लगे। पीड़ित जब पिज्जा की ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, तभी एक आरोपी ने उसे पकड़ लिया।

विरोध करने पर आरोपी पिटाई कर मोबाइल लूटकर ले गए। न्यू अशोक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान इंस्पेक्टर केके शर्मा की टीम ने मयूर विहार फेज-तीन व धारोली में दबिश देकर एक नाबालिग को पकड़ लिया। उसके कब्जे से युवक से लूटा गया मोबाइल, टॉय गन व चोरी की स्कूटी बरामद हो गई।

पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने दो नाबालिगों को भी पकड़ लिया। इनके कब्जे लूटे गए तीन और मोबाइल बरामद किए गए। आरोपी प्रेमिकाओं पर पैसा लुटाने के लिए वारदात करते थे। ये नशा करने के भी आदि है। आरोपियों से बरामद स्कूटी दिसंबर में चुराई गई थी।

मुंबई में जलसंकट गहराने के आसार!

मुंबई : जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण अनमोल पानी का संकट गहराता जा रहा है। इससे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी अछूती नहीं रही है। अपने आस-पास की झीलों के पानी पर पूरी तरह से निर्भर मुंबई में भविष्य में जलसंकट गहराने के आसार हैं। इससे संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में पानी को लेकर जंग छिड़ सकती है। मुंबई की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। शहर में गगनचुंबी इमारतें, पंचसितारा होटलों,

हाई प्रोफाइल सोसाइटियों और बस्तियों में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। कई आवासीय इलाकों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होती है। लाखों लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं और पानी के टैंकर पर निर्भर हैं। पानी की मांग और आपूर्ति दोनों संतुलन दिन-ब-दिन बिगड़ता जा रहा है। मुंबई मनपा शहर को प्रतिदिन ४,२०० मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होने के बावजूद केवल ३,८५० मिलियन लीटर प्रतिदिन की आपूर्ति करती है। इलाकों में बोरवेल से पानी खींचकर

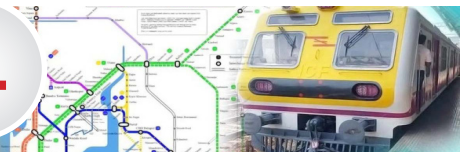


लगभग २ हजार टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पानी को लेकर विवाद होने की घटनाएं आए

दिनों होती रहती हैं। साथ ही जिन झीलों से मुंबई को जलापूर्ति होती है, उसके आस-पास के लोग पानी के अधिकार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। यदि भविष्य में जलसंकट बढ़ता है तो यह संघर्ष और बढ़ने की संभावना है।

वर्तमान में मुंबई में प्रतिदिन ३,८५० मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति होती है। इसमें से २७ प्रतिशत यानी लगभग ८०० मिलियन लीटर पानी रिसाव व चोरी के कारण बर्बाद हो जाता है। पिछले तीन वर्षों पर गौर करें तो

वर्ष २०२१ में ५७, ९५३ मिलियन लीटर, वर्ष २०२२ में ६,३०,५६२ मिलियन लीटर और वर्ष २०२३ में ५,८८,३८९ मिलियन लीटर पानी का भंडारण हुआ था। मौजूदा समय में मुंबई को जलापूर्ति करने वाली झीलों भातसा में २,८३,३७, अपर वैतरणा में १,३७,१४, मोडक सागर में ४४,००४, मध्य वैतरणा में ३१,७००, तानसा में ७४,७८२, विहार में १३,६४५ और तुलसी झील में ४,२०८ मिलियन लीटर जल भंडारण उपलब्ध है।



मीरा भायंदर और नवी मुंबई में 24 और 25 मार्च को बंद रहेगी पानी की सप्लाई



मुंबई : मुंबई के कुछ इलाकों को अगले 24 घंटों के लिए पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। दरअसल, मुंबई के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। बता दें कि मुंबई के नवी मुंबई और मीरा भायंदर में 24 और 25 मार्च को पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। 24 मार्च को मुंबई महानगर क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तरफ से नवी मुंबई और मीरा भायंदर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर मरम्मत के कुछ काम होंगे, जिसके कारण मुंबई के कुछ इलाकों में 24 और 25 मार्च

को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार नवी मुंबई और मीरा भायंदर के इलाकों में तत्काल पानी की पाइप लाइन का काम करेगा। 24 मार्च को दोपहर 12 बजे से अगले 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि पाइप लाइन खराब हो गई है। जिसको तत्काल में बदलने का काम किया जाएगा और पाइप को बदलने का काम किया जाएगा।

अगले 24 घंटे ठप रहेगी पानी की सप्लाई
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास

निगम के अधिकारियों के अनुसार मुंबई में पाइप लाइन में गड़बड़ी आ गई है। जिसको सही करने का काम चालू किया जाएगा। मुंबई में पानी होने के कारण सप्लाई होने वाले पाइप लाइन में परेशानी आ गई है। इन सब कामों को 24 और 25 मार्च के बीच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई और मीरा भायंदर नगर निगम में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी।

पानी का स्टॉक कर करें सहयोग
पानी लीकेज को रोकने के चलते 24 मार्च से लेकर 25 मार्च तक मुंबई में पानी की भारी कमी रहेगी। इन नगर निगम के लोग अभी से पानी भर कर अपने-अपने घरों में रख रहे हैं। पानी की कटौती से प्रभावित नवी मुंबई और मीरा भायंदर नगर निगम क्षेत्र है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने लोगों से अपील की है कि वे लोग 23 मार्च को ही 24 और 25 मार्च के लिए अपने घरों में पर्याप्त मात्रा में पानी का स्टॉक कर सहयोग करें।

विधानसभा में राहुल गांधी के पोस्टर को चप्पलों से मारने पर विवाद

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा में महा विकास आघाड़ी के विधायकों ने महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर की सीढ़ियों पर राहुल गांधी के पोस्टर को कथित तौर पर चप्पलों से मारने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना के सदस्यों की बृहस्पतिवार को आलोचना की। सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंदुत्व विचारक वी. डी. सावरकर को लेकर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गांधी के पोस्टर पर कथित तौर पर चप्पलें मारी थीं।

महा विकास आघाड़ी (एमवीए) में शिवसेना (उद्धव ठाकरे नीत गुट), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की इस हरकत पर नाराजगी जताई और जांच का वादा किया। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसका नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने स्वागत किया। दोनों ने सत्तारूढ़ पार्टी



के सदस्यों के व्यवहार को असंसदीय करार देते हुए इसकी आलोचना की।

थोराट ने इस कृत्य में शामिल विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वीकार किया कि विधान भवन परिसर में इस तरह के कृत्य करना गलत है, लेकिन साथ ही गांधी की आलोचना की। फडणवीस ने कहा कि सावरकर ने अंडमान में 11 साल जेल में बिताए थे और उन पर गांधी की टिप्पणी की निंदा की जानी चाहिए। भाजपा के विधायक अतुल भटखल्कर ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोबारा शुरू होने पर कहा, "अपराधिक मामले में जमानत पर रिहा व्यक्ति

स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर रहा है।

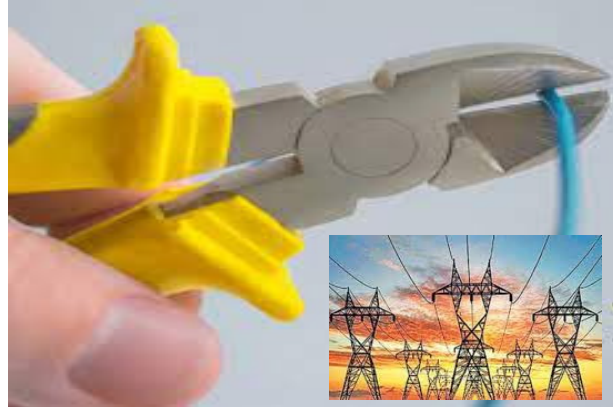
इस बीच अध्यक्ष नावेंकर ने कहा, "मैं मामले की जांच करूंगा और रिकॉर्डिंग भी देखूंगा। यह दोबारा नहीं होना चाहिए अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्तारूढ़ विधायकों की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा, "अगर आप निंदा करना चाहते हैं तो उचित मंच पर करें। अभी तक (मामले पर कार्रवाई के लिए) मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। इससे पहले, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों द्वारा सावरकर पर गांधी की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ नारेबाजी के कारण दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी में लगी आग, दो कर्मचारी झुलसे



पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में बृहस्पतिवार सुबह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की एक कंपनी में आग लग गई, जिससे दो लोग झुलस गए। पालघर दमकल विभाग के अधिकारी दिनेश अंबुरे ने मीडिया को बताया कि आग तारापुर एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी के रिएक्टर में सुबह करीब साढ़े छह बजे लगी। इस दर्दनाक घटना में दो कर्मचारी झुलस गए। उन्होंने कहा, "दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर दो घंटे के भीतर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है।

नहीं कटेंगे स्कूलों के बिजली कनेक्शन



मुंबई। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधानसभा में कहा कि बिजली विभाग को स्कूलों के कनेक्शन नहीं काटने के निर्देश दिए जाएंगे। मंत्री ने स्वीकार किया कि पालघर, जलगांव, नाशिक, नंदूरबार जिलों सहित राज्य के 9262 स्कूल बिजली के अभाव में अंधेरे में हैं। गुरुवार को प्रश्नोत्तर काल में भाजपा के सुनील राणे, आशीष शेलार, कांग्रेस के अशोक

चव्हाण, विपक्ष के नेता अजित पवार सहित अन्य सदस्यों ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर सवाल किए थे। विधायकों के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य जिला परिषद पर बिजली बिल की बकाया रकम 18.56 करोड़ रुपए थी, जिसका भुगतान कर दिया गया है। केसरकर ने कहा कि स्कूलों की बिजली काटना दर्भाग्यपूर्ण है।

इस बारे में कैबिनेट में चर्चा कर स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम

केसरकर ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार विशेषज्ञों की समिति गठित करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल फीस तय होगी। वर्तमान में स्कूलों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों के बीच आपसी विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया जाता है। विधानसभा में विधायकों ने पुणे के वाघोली में स्थित द लैक्सिकॉन इंटरनेशनल स्कूल में 200 विद्यार्थियों को फीस न भरने के चलते एक कमरे में बिठाकर रखने और अभिभावकों के आने के बाद उन्हें छोड़ने से जुड़ा सवाल पूछा था। केसरकर ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि कोई भी अभिभावक बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा, इसलिए पुलिस ने जांच बंद कर दी।

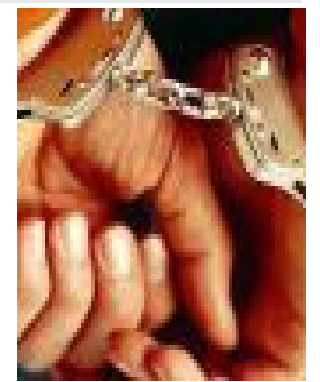
जमानत पर छूटा हिस्ट्रीशीटर फिर गिरफ्तार...

चोरी का ऑटोरिक्षा बेचने की फिराक में था आरोपी

ठाणे : मुंबई के ठाणे में ऑटोरिक्षा चोरी के आरोप में एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी चोरी का रिक्शा बेचने के लिए कल्याण इलाके में पहुंचा हुआ था। जहां सुचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है, जो जमानत पर जेल से बाहर है।

पुलिस ने ऑटोरिक्षा किया जब्त

पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 21 है और वो पेशे से राजमिस्त्री का भी काम करता है। उसे बुधवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया, वह चोरी का ऑटोरिक्षा बेचने के लिए कल्याण



आया था। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए ऑटोरिक्षा को जब्त कर लिया गया है। आरोपी 9 मार्च को ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। उसने मानपाड़ा, वर्तक नगर, कोलसेवाडी, बाजारपेठ और एमएफसी पुलिस थानों की सीमाओं में अपराध किए हैं।